भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3166

06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

एनयूडीएम की स्थिति

†3166. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें शामिल किए गए राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की संख्या कितनी है और उनके डिजिटल एकीकरण का राज्य-वार और शहरी स्थानीय निकाय-वार स्तर क्या है;

(ख) क्या किन्हीं राज्य सरकारों अथवा शहरी स्थानीय निकायों ने राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन में शामिल होने अथवा उसका विस्तार करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं और यदि हां, तो राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए, कितने प्रस्ताव अनुमोदित और लंबित हैं और विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान एनयूडीएम पहलों के लिए आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और लंबित राशि अथवा कम उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) एनयूडीएम के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाओं जैसे संपत्ति कर, उपयोगिता भुगतान, नागरिक शिकायत निवारण और ई-गवर्नेंस प्लेटफार्मों के साथ-साथ निष्पादन मैट्रिक्स और प्रयोक्ता अपनाने संबंधी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) एनयूडीएम के कार्यान्वयन में राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है; और

(च) शहरी स्थानीय निकायों के पूर्ण एकीकरण के लिए भावी रूपरेखा और समय-सीमा क्या है जिसमें शहरों में नागरिक भागीदारी, डिजिटल समावेशिता और पारस्परिकता की योजना क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (च): वर्तमान में, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) अपने प्रायोगिक चरण में है। फरवरी, 2021 में प्रारंभ किए गए इस पायलट का उद्देश्य नागरिक-केंद्रित शहरी

डिजिटल प्लेटफॉर्म, अर्थात् ऑनलाइन गवर्नेंस की प्रदायगी हेतु शहरी प्लेटफॉर्म (उपयोग), का विकास करना है, जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। उपयोग एक ओपन-सोर्स, माइक्रोसर्विस-आधारित और मॉड्यूलर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें ई-गवर्नेंस समाधानों का एक समूह शामिल है, जो शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को डिजिटल नगरपालिका सेवाएँ प्रदान करने में सहायता करता है। इसकी संरचना इंटरऑपरेबिलिटी, मौजूदा राज्य और नगरपालिका प्रणालियों के साथ निर्बाध एकीकरण तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सरल अनुकूलन में सहयोग करती है। केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एनयूडीएम के कार्यान्वयन हेतु पिछले तीन वर्षों में किए गए वर्ष-वार वित्तीय आवंटन नीचे दिए गए हैं। तथापि, मिशन के प्रारंभ न किए जाने के कारण आवंटित निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका है।

(करोड़ में)

वर्ष	**बीई**	**आरई**	**व्यय**
2024-25	1150	108.70	0
2025-26	1250	0	0
2026-27	300	लागू नहीं	लागू नहीं

***